

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

सातवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

सातवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज (27 मार्च 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.40 कर दिया जाए।
- तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.40 प्रतिशत से घटकर 4.65 प्रतिशत हो गई;
- इसके अलावा, विकासात्मक और विनियामक नीतियों में उल्लिखित किए अनुसार एलएएफ कॉरिडोर के विस्तार के परिणामस्वरूप एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 90 आधार अंक घटकर 4.0 प्रतिशत हो गया।
- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

* 27 मार्च 2020 को जारी किया गया।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. वैश्विक आर्थिक गतिविधि ठहराव की स्थिति में आ गई है क्योंकि सभी प्रभावित देशों में COVID-19 संबंधित लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग व्यापक स्तर पर लगाई गई है। 2019 के दशक में मंद वैश्विक विकास को 2020 में अल्प वसूली की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। महामारी की तीव्रता, प्रसार और अवधि की संभावनाएं अब काफी आकस्मिक है। इस बात की संभावना बढ़ रही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा मंदी की चपेट में आ जाएगा।

3. COVID-19 के प्रकोप के कारण जनवरी से वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिर हो गए हैं। पैनिक सेल-ऑफ ने सम्पूर्ण उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में समान रूप से धन का नाश किया है। पूर्व में, सुरक्षा की ओर रुख के कारण हाल के दिनों में कुछ सख्ती के साथ सरकारी बांड प्रतिफल में कमी दर्ज की गई। उत्तरार्द्ध में, बाहर निकलने की जल्दबाज़ी ने नियत आय बाजारों को निरूपित किया है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिफल में वृद्धि हुई है। अत्यधिक जोखिम के कारण त्वरित बिक्री के वजह से उभरते और उन्नत अर्थव्यवस्था की मुद्राओं को दैनिक आधार पर गंभीर मूल्यहास दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में, केवल अमेरिकी डॉलर अत्यधिक अनिश्चित संभावनाओं में सुरक्षित बना हुआ है। मार्च के आरंभ तक अन्य दो-जापानी येन और सोना जो सुरक्षित थे, नकदी में बढ़ोत्तरी की ओर रुख किया। COVID-19 के प्रकोप के कारण मांग कमजोर पड़ने की आशंका में जनवरी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आरंभ में सौम्य भाव से कारोबार हुआ। हालांकि, प्रमुख तेल उत्पादकों के बीच उत्पादन में कटौती ने असहमति को बढ़ा दिया है, प्रतिशोधी सप्लाई स्केल-अप और मूल्य युद्ध के कारण 18 मार्च 2020 को अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमतें 25 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गई हैं। इन घटनाओं से उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय बैंक और सरकार युद्ध मोड में हैं, चलनिधि के कारण मांग में गिरावट से बचने के लिए और वित्तीय बाजारों को बंद होने से बचाने के लिए वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए लक्षित कई पारंपरिक और अपारंपरिक उपायों के साथ स्थिति का जवाब दे रहे हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. फरवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2019-20 के चौथे तिमाही के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 4.7 प्रतिशत लगाया गया, जो कि पूरे वर्ष के लिए 5 प्रतिशत के वार्षिक अनुमान के भीतर है। इस पर भी अब अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के कारण जोखिम मंडरा रहा है। उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि निजी अंतिम खपत व्यय को गहरा झटका लगा है, यहां तक कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी 2019-20 की दूसरी तिमाही के बाद से संकुचन में रहा है। आपूर्ति पक्ष पर, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की संभावनाएं ही केवल एक उम्मीद की किरण है, जिसमें खाद्यान्न का उत्पादन 292 मिलियन टन है जो एक साल पहले की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक है। निर्माण और बिजली उत्पादन में संवृद्धि ने पिछले पांच महीनों में अनिरंतर संकुचन और / या निष्प्रभाव गतिविधि के बाद जनवरी 2020 में औद्योगिक उत्पादन को सकारात्मक क्षेत्र में खींच लिया; हालांकि, यह जानने के लिए और अधिक डेटा को देखना होगा कि COVID-19 के सामने हाल का इजाफा टिकेगा के नहीं। इस बीच, जनवरी और फरवरी 2020 के लिए अधिकांश सेवा क्षेत्र के संकेतकों में मंदी या गिरावट आई। तब से वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि व्यापार, पर्यटन, एयरलाइंस, आतिथ्य क्षेत्र और निर्माण जैसी कई सेवाओं पर महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के विस्थापन के परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी गतिविधि में कमी आएगी।

5. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति, जनवरी 2020 में चरम पर पहुंच गई और फरवरी 2020 में पूर्ण प्रतिशत के स्तर से गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गई, क्योंकि प्याज की कीमतों में गिरावट ने पूर्ववर्ती दो महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति को दोहरे अंक से नीचे ला दिया। हालांकि, मूल्य दबाव सभी प्रोटीन युक्त वस्तुओं, खाद्य तेलों और दालों के लिए स्थिर बने रहे; लेकिन COVID-19 से मांग में आने वाली गिरावट उन्हें आगे जाकर कमजोर कर सकता है। फरवरी में अंतरराष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में देरी के घरेलू समायोजन के कारण ईंधन की मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई, मार्च में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से राहत मिल सकती है। खाद्य और ईंधन को

छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में परिवहन और संचार, और व्यक्तिगत देखभाल के सौम्य कीमतों के कारण कम हो गई। रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के मार्च 2020 के दौर में एक वर्ष आगे के परिवारों की मुद्रास्फीति संभावनाएं 20 बीपीएस तक सौम्य हो गईं।

6. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बड़े पैमाने पर अपविक्रय का सामना करने वाले इक्विटी बाजारों के साथ घरेलू वित्तीय स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई है। बांड बाजार में भी प्रतिफल निरंतर एफपीआई की बिक्री पर बढ़ी है, जबकि मोचन दबाव, ट्रेडिंग गतिविधि में गिरावट और सामान्यीकृत जोखिम के फैलाव ने वाणिज्यिक पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य नियत आय वाले क्षेत्रों में ऊंचे स्तर तक प्रतिफल को बढ़ावा दिया है। विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) निरंतर नीचे की ओर दबाव में रहा है। इन परिस्थितियों में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों को तरल, स्थिर और कामकाज को सामान्य रूप से बनाए रखने का प्रयास किया है। एलएएफ के तहत निवल अवशोषण में परिलक्षित प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष मार्च में औसतन 2.86 लाख करोड़ (25 मार्च 2020 तक) था। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने ₹ 11,724 करोड़ की संचयी निवल राशि उपलब्ध कराते हुए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (₹ 28,276 करोड़) की समान बिक्री और दीर्घावधि प्रतिभूतियों (₹ 40,000 करोड़) की खरीद को शामिल करते हुए 'ट्रिस्ट ऑपरेशन' नामक नीलामी के रूप में अपरंपरागत परिचालन आरंभ किया। रिजर्व बैंक ने चलनिधि उपलब्ध कराने और मौद्रिक संचरण में सुधार करने के लिए अब तक 1.25 लाख करोड़ के संचयी राशि के 1 वर्ष और 3 वर्ष के कार्यकाल के पांच दीर्घकालिक रेपो नीलामी का भी आयोजन किया। रिजर्व बैंक ने 16 और 23 मार्च को 2.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बाजार में संचयी रूप से अमेरिकी डॉलर चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए दो बिक्री-खरीद स्वैप नीलामी का भी संचालन किया। चलनिधि को मजबूत करने और वित्तीय स्थितियों को सरल बनाने के लिए 20 मार्च को ₹ 10,000 करोड़ और 24 मार्च तथा 26 मार्च दोनों को ₹ 15,000 करोड़ का खुला बाजार खरीद परिचालन आयोजित किया गया।

7. बाहरी क्षेत्र में, पण्य का निर्यात फरवरी 2020 में लगातार छह महीने के संकुचन के बाद विस्तारित हुआ। आठ महीने की

लगातार गिरावट के बाद आयात वृद्धि भी सकारात्मक दिखाई दी। फलस्वरूप, व्यापार घाटा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मामूली रूप से बढ़ा, हालांकि यह एक महीने पहले अपने स्तर से कम था। 12 मार्च को, रिजर्व बैंक ने भुगतान का संतुलन डाटा जारी किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि चालू खाता, जीडीपी के केवल 0.2 प्रतिशत की कमी के साथ क्यू3: 2019-20 में दर्शाए शेष के समीप था। वित्त पोषण के संबंध में, अप्रैल-जनवरी 2019-20 के दौरान 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफडीआई अंतर्वाह एक वर्ष पूर्व की तुलना में काफी अधिक था। संविभाग निवेश ने 2019-20 (25 मार्च तक) के दौरान 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्गमन में गिरावट दर्ज की, जो एक वर्ष पहले 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 6 मार्च 2020 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 487.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया – जो उनके मार्च 2019 के अंत के स्तर से 74.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक था।

आउटलुक

8. फरवरी 2020 के छठे द्विमासिक संकल्प में, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति क्यू4: 2019-20 के लिए 6.5 प्रतिशत पर अनुमानित की गई थी। जनवरी और फरवरी 2020 के प्रिंट्स से पता चलता है कि तिमाही के लिए वास्तविक परिणाम प्याज की कीमत को दर्शाते हुए, अनुमानों से 30 बीपीएस ऊपर चल रहे हैं। आगे, रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन के लाभकारी प्रभावों के तहत, कम से कम सामान्य गर्मियों की शुरुआत तक, खाद्य पदार्थों की कीमतें और भी नरम हो सकती हैं, इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ईंधन और मूल मुद्रास्फीति दोनों दबावों को कम कर सकेगा, जोकि खुदरा कीमतों के पास-थ्रू के स्तर पर निर्भर होगा। COVID-19 के परिणामस्वरूप, सकल मांग कमजोर हो सकती है और मूल मुद्रास्फीति को और कम कर सकती है। वित्तीय बाजारों में ऊँची अस्थिरता का असर मुद्रास्फीति पर भी पड़ सकता है।

9. विकास की ओर मुड़ते हुए, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की निरंतर आघात-सहनीयता के अलावा, अर्थव्यवस्था के अधिकांश अन्य क्षेत्रों पर महामारी द्वारा, इसकी तीव्रता, प्रसार और अवधि के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि COVID-19 लंबे सामी तक रहा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, तो

वैश्विक मंदी भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव के साथ गहरा सकती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, व्यापार लाभ के रूप में कुछ राहत प्रदान कर सकती है। COVID-19 और लंबे समय तक लॉकडाउन के प्रसार से विकास के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न होते हैं। मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य नीतिगत उपायों और COVID -19 के शुरुआती नियंत्रण से अधिक वृद्धि आवेग उत्पन्न होने की उम्मीद है।

10. एमपीसी का विचार है कि, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर, महामारी द्वारा लाए गए व्यापक आर्थिक जोखिम गंभीर हो सकते हैं। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि, घरेलू अर्थव्यवस्था को महामारी से बचाने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है, उसे करना चाहिए। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक और विनियामक उपाय - पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों किए हैं। दुनिया भर में सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए लक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के समर्थन सहित बड़े पैमाने पर राजकोषीय उपाय किए हैं। वायरस के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों सहित किसानों, प्रवासी श्रमिकों, शहरी और ग्रामीण गरीबों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण और अन्न सुरक्षा सहित ₹ 1.70 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज, की घोषणा की है। एमपीसी ने यह देखा है कि रिजर्व बैंक ने प्रणाली में पर्याप्त तरलता को इंजेक्ट करने के लिए कई उपाय किए हैं। बहरहाल, महामारी के प्रतिकूल व्यापक आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करने को प्राथमिकता देनी होगी। एमपीसी इस संदर्भ में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में भारी कमी के लिए वोट करता है, लेकिन कमी की मात्रा में कुछ असहमति के साथ। इसके अलावा, एमपीसी यह भी नोट करता है कि रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में तरलता, मौद्रिक संचरण और ऋण प्रवाह को और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को शुरू करने का निर्णय लिया है और ऋण शोधन पर राहत प्रदान की है। यह सभी हितधारकों के लिए महामारी से लड़ने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को वायरस द्वारा लगाए गए अलगाव के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे आर्थिक एजेंटों को क्रेडिट प्रवाहित करने के

लिए जो संभव हो करना चाहिए। बाजार सहभागियों को भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे नियामकों के साथ काम करना चाहिए ताकि मूल्य खोज और वित्तीय मध्यस्थता की उनकी भूमिका में बाजारों के क्रमबद्ध कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। स्थिति से निपटने के लिए मजबूत राजकोषीय उपाय महत्वपूर्ण हैं।

11. यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, सभी सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव

को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए वोट किया।

12. डॉ. रविन्द्र एच.ढोलाकिया, डॉ. जनक राज, डॉ. माइकल देबब्रता पात्र, श्री शक्तिकांता दास ने नीतिगत रेपो दर में 75 बीपीएस कटौती के लिए वोट किया। डॉ. चेतन घाटे और डॉ.पमी दुआ ने नीतिगत रेपो दर में 50 बीपीएस कटौती के लिए वोट किया।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 13 अप्रैल 2020 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

इस वक्तव्य में अनेक प्रकार की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियां शामिल की गई हैं, जो COVID-19 के कारण वित्तीय स्थितियों में उत्पन्न दबावों का सीधे-सीधे समाधान प्रस्तुत करती हैं। इनमें शामिल हैं (i) प्रणाली में काफी मात्रा में चलनिधि का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 संबंधी जो अव्यवस्था पैदा हुई है उसके चलते वित्तीय बाजार और संस्थाएं सामान्य रूप से कार्य कर सकें (ii) मौद्रिक प्रसारण को बढ़ाना ताकि क्रेडिट का प्रवाह आसानी से हो सके और वे संस्थाएं स्वयं को बहाल रख सकें जो महामारी (पेंडेमिक) से प्रभावित हुई है। (iii) चुकौती संबंधी दबावों को रियायत बरतते हुए तथा कार्यशील पूंजी तक बेहतर एक्सेस प्रदान करते हुए COVID-19 की बाधाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय दबावों को कम करना तथा (iv) महामारी के चलते और उसके फैलने से बाजारों में उत्पन्न उच्च अस्थिरता को देखते हुए बाजारों की कार्यात्मकता को बेहतर बनाना इस भाग में दी गई नीतिगत पहल को मौद्रिक नीति कार्रवाई और समाधान स्वरूप उसके रुझान के संबंध में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

I. चलनिधि प्रबंधन

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपायों की पहली खेप से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी प्रकार के घटकों को पर्याप्त मात्रा में चलनिधि उपलब्ध हो ताकि COVID-19 की वजह से पैदा चलनिधि बाधाएं सहज बन सकें।

1. लक्ष्य किए गए दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

भारत में COVID-19 के फैलने और तेजी से हुए उसके प्रसार ने घरेलू इक्विटी, बॉण्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में भारी बिक्री को और भी तीव्र कर दिया। शोधन के तीव्र दबाव के कारण लिखतों पर चलनिधि प्रक्रिया जैसे कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर और डिबेंचर पर प्रीमियम बढ़ते चले गए। इसके साथ, COVID-19 के फैलने से व्यापार संबंधी गतिविधियाँ कम हो जाने को मिलाकर देखा जाए तो इन लिखतों की वित्तीय स्थिति भी, अन्य बातों के साथ-साथ बैंक क्रेडिट की हालत मंद हो जाने की स्थिति में कार्यशील पूंजी को एक्सेस कर पाना भी कठिन हो गया। आर्थिक गतिविधियों पर इनके प्रतिकूल प्रभावों, जिससे नकदी प्रभावों पर दबाव पड़ता है, को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है

कि रिजर्व बैंक उपयुक्त आकार के लक्ष्य किए गए तीन वर्ष तक के सावधि रेपो की नीलामियाँ करेगा जिसकी कुल राशि 1,00,000 करोड़ रुपए होगी और जो नीतिगत रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर आधारित होगी।

बैंको द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई चलनिधि को निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर में लगाना होगा जो 27 मार्च 2020 को उनके द्वारा इन बॉण्डों में किए जाने वाले निवेश के बकाया स्तर के अतिरिक्त होगा। बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पात्र लिखतों की अपनी वृद्धिशील धारिता का पचास प्रतिशत तक प्राथमिक बाजार के निर्गमों से प्राप्त करें और शेष पचास प्रतिशत म्यूचुअल फंड एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित द्वितीयक बाजार से प्राप्त करें। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कुल अनुमत निवेश 25 प्रतिशत से अधिक क्यों न हो। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए एक्सपोजर की गणना बड़े एक्सपोजर प्रेमवर्क के अधीन नहीं की जाएगी।

टीएलटीआरओ की पहली नीलामी आज (27 मार्च 2020) को की जाएगी। इस नीलामी के परिणामों की समीक्षा के बाद आगामी टीएलटीआरओ नीलामियों की घोषणा की जाएगी।

इस सुविधा की जानकारी अलग से जारी की जा रही है।

2. नकदी प्रारक्षित अनुपात

ए. बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि प्रचूरता से बनी रहेगी जैसाकि 1 से 25 मार्च 2020 के दौरान दैनिक औसत आधार पर 2.86 लाख करोड़ रुपए एलएएफ रिवर्स रेपो परिचालन के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष को अवशोषित करने से परिलक्षित होता है। लेकिन यह पाया गया है कि चलनिधि का यह वितरण संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक असमान है और वह भी स्पष्टतया बैंकिंग प्रणाली के भीतर है।

COVID-19 से उत्पन्न बाधाओं के कारण तंगहाली में पड़े बैंकों की एकबारगी सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित निधि (सीआरआर) को 28 मार्च 2020 को प्रारंभ रिपोर्टिंग पखवाड़े से 100 आधार अंक कम कर के निवल माँग और मियादी देयताओं

(एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत कर दिया जाए। सीआरआर में की गई इस कमी से संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए की प्राथमिक चलनिधि आ जाएगी जो घटकों की अतिरिक्त एसएलआर की धारिता के सापेक्ष न हो कर उनकी देयताओं के अनुपात में होगी। यह छूट 26 मार्च 2021 को समाप्त एक वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी।

बी. इसके अतिरिक्त, स्टाफ की सामाजिक दूरी की वजह से बैंकों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके फलस्वरूप रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले दिन से प्रभावी न्यूनतम दैनिक सीआरआर की अपेक्षा को घटाकर 90 से 80 प्रतिशत कर दिया जाए। यह छूट एकबारगी रूप में 26 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

3. सीमांत स्थायी सुविधा

सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत बैंक, अपने विवेक पर संविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से 2 प्रतिशत तक ओवरनाइट उधार ले सकते हैं। घरेलू वित्तीय बजार में अपवाद रूप से अत्यधिक अस्थिरता की हालत ने चलनिधि पर चरणबद्ध रूप से दबाव पैदा कर दिया है, बैंकिंग प्रणाली को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सीमा को तत्काल प्रभाव से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाए। यह उपाय 30 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगा। इसके पीछे मंशा यह है कि मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में घोषित एमएसएफ की घटी हुई दर पर दबाव की हालत में बैंकिंग प्रणाली को एलएएफ विंडो के अंतर्गत 1,37,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएँ ताकि उसमें सहजता पैदा हो।

टीएलटीआरओ, सीआरआर और एमएसएफ इन तीनों उपायों से प्रणालियों में कुल 3.74 लाख करोड़ रुपए की चलनिधि आ जाएगी।

4. मौद्रिक नीति दर के कॉरिडॉर को बढ़ाना

यह निर्णय लिया गया है कि लगातार बनी हुई अधिशेष चलनिधि की स्थिति में वर्तमान नीतिगत कॉरिडॉर को 50 आधार अंक

से बढ़ा कर 65 आधार अंक कर दिया जाए। इस नए कॉरिडॉर के अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 40 आधार अंक होगी जो नीतिगत रेपो दर से कम होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) 25 आधार अंक पर नीतिगत रेपो दर से अधिक बनी रहेगी।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

चलनिधि संबंधी उपायों के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि COVID-19 महामारी के संकट के कारण उत्पन्न बाधाओं की वजह से कर्ज चुकाने के बोझ को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। इस प्रकार के प्रयासों से वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के प्रसार पर रोक लगेगी और इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कारोबार फायदेमंद तरीके से चलते रहें और ऐसी कठिन घड़ी में उधारकर्ताओं को राहत मिल सके।

5. मीयादी ऋणों का स्थगन

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं तथा एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनी तथा माइक्रो वित्त कंपनी सहित) ("उधारदाता संस्थाएं") को अनुमति दी जाती है कि वे 1 मार्च 2020 को बकाया सभी मीयादी ऋणों पर किश्तों के भुगतान पर तीन महीने के स्थगन की अनुमति प्रदान करें। तदनुसार, चुकौती के सभी शैड्यूल तथा बाद की सभी देय तारीखें, तथा इस प्रकार के ऋणों की अवधि सभी स्तरों पर तीन महीने के लिए आगे बढ़ जाएगी।

6. कार्यशील पूंजी सुविधा पर ब्याज आस्थगित करना

उधार देने वाली संस्थाओं को यह अनुमति दी जाती है कि कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट के संबंध में 1 मार्च 2020 को बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के लिए ब्याज के भुगतान की तारीख तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दें। इस अवधि के लिए संचित ब्याज का भुगतान आस्थगित अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा।

उपर्युक्त पैरा 5 और 6 के संबंध में, स्थगन/ आस्थगन की सुविधा विशेष रूप से इसलिए प्रदान की जा रही है, ताकि उधारकर्ता COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपट सकें। अतः इसे उधारकर्ताओं की वित्तीय परेशानी के कारण ऋण हेतु किए गए

करार की शर्तों में परिवर्तन नहीं माना जाएगा और फलस्वरूप आस्तियों का निम्न श्रेणी में वर्गीकरण नहीं करना होगा। उधारदाता संस्थाएं इस संबंध में तदनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति कार्यान्वित कर सकते हैं।

7. कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण को आसान बनाना

कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधा के संबंध में उधारदाता संस्थाएं आहरण- शक्ति की पुनःगणना मार्जिन कम करते हुए और/ अथवा उधारकर्ता के लिए कार्यशील पूंजी के चक्र का पुनर्मूल्यांकन करते हुए करें। विशेष रूप से COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए उधारकर्ताओं को क्रेडिट-शर्तों में बदलाव करने हेतु दी गई अनुमति को उनकी वित्तीय कठिनाई के कारण प्रदान की गई रियायत नहीं माना जाएगा और फलस्वरूप आस्तियों का वर्गीकरण निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा।

पैरा 5, 6 और 7 के संबंध में भुगतान के पुनर्निर्धारण को पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग के प्रयोजन से तथा (सीआईसी) उधारदाता संस्थाओं द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्टिंग के प्रयोजन से चूक नहीं माना जाएगा। सीआईसी यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त घोषणा के अनुसरण में उधारदाता संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई का लाभार्थियों के क्रेडिट-इतिहास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

8. निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को स्थगित करना

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में किए गए सुधारों के एक हिस्से के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसेल समिति (बीसीबीएस) ने निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की थी, जो भविष्य के वित्तपोषण तनाव के जोखिम को कम करने के लिए एक वर्ष के समय क्षितिज पर वित्तपोषण के पर्याप्त स्थायी स्रोतों से बैंकों के कार्यकलाप को वित्त पोषित कर बैंकों की आवश्यकता के हिसाब से जोखिम को कम करता है। निर्धारित समयावधि के अनुसार, भारत में बैंकों को 1 अप्रैल 2020 से एनएसएफआर को 100 प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता थी। अब 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छह महीने तक एनएसएफआर के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

9. पूंजी संरक्षण बफर के अंतिम ट्रेंच का स्थगन

पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक सामान्य समय के दौरान (यानी, तनाव के समय के बाहर) पूंजीगत बफर का निर्माण करें, जिन्हें एक तनावग्रस्त अवधि के दौरान होने वाले नुकसान के लिए निकाला जा सकता है। बेसल मानकों के अनुसार, सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के ट्रेंच में लागू किया जाना था और 2.5 प्रतिशत के पूर्ण सीसीबी में परिवर्तन 31 मार्च 2019 तक पूरा होना तय था। बाद में 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। COVID-19 के कारण संभावित तनाव को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, अतिरिक्त टियर 1 लिखत (पीएनसीपीएस और पीडीआई) रूपांतरण / राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित ट्रिगर जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

III. वित्तीय बाजार

वित्तीय बाजारों के संबंध में निर्णय अनिवार्य रूप से एक विकासात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य और ओनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच मध्यस्थता को कम करके विदेशी मुद्रा बाजार क्षेत्रों में गहनता और मूल्य खोज में सुधार करना है। यह उपाय मुद्रा बाजारों पर COVID-19 के प्रभाव के कारण रुपये की बढ़ी हुई अस्थिरता के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है।

10. बैंकों को ऑफशोर गैर-सुपुर्द रुपया डेरिवेटिव बाजार (ऑफशोर एनडीएफ रुपया बाजार) में डील करने की अनुमति देना

ऑफशोर भारतीय रुपया (आईएनआर) डेरिवेटिव बाजार - गैर-सुपुर्द वायदा (एनडीएफ) बाजार हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में, भारतीय बैंकों को इस बाजार में भाग लेने की अनुमति नहीं है, हालांकि एनडीएफ बाजार में उनकी भागीदारी के लाभों को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। मुद्दे के सभी पहलुओं

की विस्तार से जांच की गई है और आरबीआई में एक आम सहमति बन गई है कि यह समय ओनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच विभाजन को हटाने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने के लिए उपयुक्त है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के परामर्श से, 1 जून 2020 से एनडीएफ बाजार में भाग

लेने की अनुमति भारत में उन बैंकों को दी जाए जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को परिचालित करते हैं। बैंक भारत में अपनी शाखाओं, अपनी विदेशी शाखाओं या अपने आईबीयू के माध्यम से भाग ले सकते हैं। आज अंतिम निर्देश जारी किए जा रहे हैं।